

सरकारी लूट, छूट आरक्षण और कर वसूली को ऐसे समझिये

सरकार द्वारा दी जा रही राहत पर एक अर्थशास्त्री की सटीक व्याख्या !

राहत पैकेज को ऐसे समझें।

एक बार 10 मित्र जिनमें कुछ फटेहाल, कुछ ठीक ठाक और कुछ सम्पन्न लग रहे थे, एक ढाबे में खाना खाने गए।

बिल आया 100 रु। 10 रु की थाली थी।

मालिक ने तय किया कि बिल की भागीदारी देश की कर प्रणाली के अनुरूप ही होगी।

इस प्रकार –

पहले 4 बेहद गरीब (बेचारे) .. फ्री

5वाँ गरीब1रु

6ठा कम गरीब3रु

7वाँ निम्न मध्यम वर्ग7रु

8वाँ मध्यम वर्ग12रु

9वाँ उच्च वर्ग18रु

10वाँ अति उच्च वर्ग.. 59रु

दसों मित्रों को ये व्यवस्था अच्छी लगी और वो उसी ढाबे में खाने लगे।

कुछ समय तक रोज़ इन दसों को आते देख कर ढाबे का मालिक बोला – “आप लोग मेरे इतने अच्छे ग्राहक हैं सो मैं आप लोगों को टोटल बिल में 20 रु की छूट दे रहा हूँ।”

अब समस्या ये कि इस छूट का लाभ कैसे दिया जाए सबको ? पहले चार तो यूँ भी मुफ्त में ही खा रहे थे।

एक तरीका ये था कि 20 रु बाकी 6 में बराबर बाँट दें तो भी बात नहीं बन पा रही थी, अगर ऐसा करते तो ऐसी स्थिति में पहले 4 के साथ 5वाँ भी फ्री हो जाता और 5 वां ₹2.33 और 6ठा ₹0.67 घर भी ले जा सकते थे मुफ्त खाने के अलावा। पर ढाबा-मालिक ने ज्यादा न्याय संगत तरीका खोजा।

नयी व्यवस्था में अब पहले 5 मुफ्त खाने लगे।

6ठा 3 की जगह 2 रु देने लगा... 33%लाभ।

7वां 7 की जगह 5 रु देने लगा...28%लाभ।

8वां 12 की जगह 9 रु देने लगा...25%लाभ

9वां 18 की जगह 14रु देने लगा...22%लाभ। और

10वां 59 की जगह 49रु देने लगा.. सिर्फ 16%लाभ।

बाहर आकर 6ठा बोला, मुझे तो सिर्फ 1 रु का लाभ मिला जबकि वो पूंजीपति 10 रु का लाभ ले गया।

5वां जो आज मुफ्त में खा के आया था, बोला वो मुझसे 10 गुना ज्यादा लाभ ले गया।

7वां बोला, मुझे सिर्फ 2 रु का लाभ और ये उद्योगपति 10 रु ले गया।

पहले 4 बोले, जो कि मुफ्त में खा रहे थेअबे तुमको तो फिर भी कुछ मिला हम गरीबों को तो इस छूट का कोई लाभ ही नहीं मिला।

ये सरकार सिर्फ इस पूंजीपति, उद्योगपति व सम्पन्न व्यक्ति के लिए काम करती है ..मारो ..पीटो ..फूंक दो....इस हरामी को और सबने मिल के दसवें को पीट दिया।

यह सम्पन्न व्यक्ति (10 वां) पिटपिटा के इलाज करवाने सिंगापुर, आस्ट्रेलिया चला गया।

अगले दिन वो ना ही उस ढाबे में खाना खाने आया और न ही लौटकर भारत आया।

और जो 9 थे उनके पास सिर्फ 40 रु थे जबकि बिल 72 रु का था।

मित्रों अगर हम लोग उन बेचारे सम्पन्न लोगों को यूँ ही पीटेंगे तो हो सकता है वो किसी और ढाबे पर खाना खाने लगे (दूसरे राज्य/ देश में चला जाए) जहां उसे कर व राहत पैकेज प्रणाली हमसे बेहतर मिल जाए।

ये है कहानी हमारे देश के कर प्रणाली, बजट व राहत पैकेज की..

मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली पानी मुफ्त सायकल, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त इलाज, मुफ्त घर....

सरकार मुफ्तखोरी की आदत लगा रही हैं जनता को ... देश ऐसे नहीं चलते...दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता किसी न किसी को तो क्रीमत चुकानी होगी।

उद्योगपतियों, पूंजीपतियों व करदाताओं को चाहे जितनी गाली दीजिये पर सच्चाई यही है कि इन्हीं करदाताओं के योगदान से देश चल रहा है।?

सोचिए, समझिए,